



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत शिवपुर हैड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी।

‘अंतिम छोर तक भरपूर नहरी पानी पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कर रही कार्य’

आईजीएनपी, भाखड़ा नहर और गंगनहर प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए दोनों बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर/श्रीगंगानगर, 9 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़- श्रीगंगानगर के अपने दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर परियोजना के अन्तर्गत शिवपुर हैड का निरीक्षण किया।

निरीक्षण करने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक भी पर्याप्त नहरी पानी पहुँचा कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरी जल पर निर्भरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आईजीएनपी, भाखड़ा नहर और गंगनहर प्रणाली के

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लम्बे समय से चली आ रही माँग को पूरा करने के लिये गंगानहर प्रणाली की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, सी.पी. लाइनिंग, फीडर पुर्ननिर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल

सुदृढीकरण के लिए गत दोनों बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों को लम्बे समय से चली आ रही माँग को पूरा करते हुए गंगनहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, सीसी लाइनिंग, फीडर पुर्ननिर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल

सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गंग केनाल ऐप और गंगनहर रेयुलेशन पोर्टल का निर्माण भी किया गया है,

जिससे नहर खुलने और बंद होने को जानकारी उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी।

शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहरों की जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण, पक्के खालों के निर्माण, बैलैस्निंग रिजर्वॉयर आदि कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में

1108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत, नोहर व भादरा तहसीलों में नहरों की जीर्णोद्धार के 128 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करवाए जा चुके हैं और 45 करोड़ रुपए के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाए जाएंगे।

श्री शिवपुर हैड स्थित महाराजा गंगासिंह जी की प्रतिमा पर गए तथा संग्रहालय का अवलोकन किया। शर्मा ने गंगनहर तथा शिवपुर हैड के निर्माण में महाराजा गंगासिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। इसके बाद, शर्मा ने शिवपुर हैड के नजदीक आयोजित प्रदर्शनों में बागवानी पद्धति, कृषि चंत्र सहित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया।

भारत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसके अन्तर्गत बाँग्लादेश ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक एक एयरबेस को नया रूप देने के लिये चीनी सहायता माँगी है। लालमोनिहर्ट – स्थित यह एयरबेस, जो चिकन नैक के नाम मशहूर संकरी सिलीगुड़ी पट्टी के नजदीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिये एक संकटपूर्ण द्वार (क्रिटिकल गेटवे) है। रिपोर्ट बता रही हैं कि बाँग्लादेश इस क्षेत्र में चीन के साथ सामरिक सहयोग की संभावनाएं खँगाल रहा है।

निर्यात सुविधा निरस्त करने के भारत के निर्णय का असर भूटान तथा नेपाल पर भी पड़ सकता है। ये देश लैन्डलॉक्ड (जमीन से घिरे हुये) हैं तथा व्यापारिक पहुँच के लिये पूरी तरह भारत के जमीनी रस्तों पर निर्भर हैं। भारत सरकार का यह निर्णय “जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के अनुच्छेद 5 के परस्पर प्रयोजनों (क्रॉस परपज) से जुड़ा प्रतीत होता है।

लेकिन ये नियम व्यापक रूप से लागू होते हैं तथा ये अप्रतिबद्ध एवं अबाधित (ऐम्बाल्यूट) नहीं हैं। एक अधिकारी ने बताया कि “कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों का हवाला दिया जा सकता है।” अधिकारी ने आगे कहा: “भारत के लिये यह जरूरी है कि वह अपनी दलीलों विशेषरूप से भूटान और नेपाल समझा दे।

कांग्रेस अधिवेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि करीब-करीब यही कहानी शेष भारत की भी है। जहाँ मोदी ने जातिगत जनगणना के लिये सहमत होने से इनकार कर दिया है, वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना हो।

मजे की बात यह है कि राहुल के भाषण के ज्यादातर हिस्से का निशाना मोदी और उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस अवसर का उपयोग उस रोड मैप पर प्रकाश डालने के लिये नहीं किया कि वे चुनाव कैसे जीतेंगे तथा भाजपा को सत्ता से बाहर कैसे करेंगे।

उनका जोर केवल डीसीसी के प्रस्तावित सशक्तिकरण पर तथा यह सुनिश्चित करने पर रहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिये पार्टी के पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया जमीनी स्तर से शुरू की जायेगी।

मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन को मजबूत बनाने का बात कहते आ रहे हैं। उनका कहना था कि केवल संगठन की मजबूती ही पार्टी के बने रहने तथा आगे बढ़ते रहने में मददगार होती है।

सूत्रों का कहना है कि यह गांधी परिवार के अंदरूनी संकट का संकेत है।

पायलट को और अधिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि जूली कहाँ है, वे यहाँ है या नहीं? इस पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष (जूली) की तलाश हुई, लेकिन वे नहीं मिले, वे संभवतः जा चुके थे। जूली से संबंधित मुद्दे पर राहुल ने कहा, “भाजपा दलितों को मंदिर में नहीं जाने देती है और अगर कोई चला जाये, तो वे मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है, जो सबको इज्जत देता है, हर व्यक्ति का आदर करता है।”

“कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है, हमारे दिलों में सबके लिये मोहब्बत और इज्जत है, जबकि उनके दिलों में सिर्फ नफ़रत। हम इस देश को नफ़रत का बाज़ार नहीं बनने देंगे- मोहब्बत को हाथे देकर जमीनी रस्तों पर निर्भर हैं। भारत सरकार का यह निर्णय “जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के अनुच्छेद 5 के परस्पर प्रयोजनों (क्रॉस परपज) से जुड़ा प्रतीत होता है।

रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से ब्याज दरों में नरमी के एक चरण की शुरुआत है। यह बात महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर, संजय मल्होत्रा ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा है कि रिज़र्व बैंक ने अब अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी (मॉड्रिक नीति) में “न्यूट्रल” (तटस्थ) रुख की जगह “अकांमोडेटीव” (उदार) रुख अपनाया है। मूल बात यही है।

प्रमुख खिलाड़ी अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़र्व बैंक की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में अधिक होगी, बजाय मूल्य के मोर्चे पर निगरानी रखने की अपनी मुख्य चिंता के। वर्तमान संदर्भ में शायद यह एक उचित रुख है, जबकि भारत की ग्राय रेट “निराशा” के दौर से उबरी है। रिज़र्व बैंक मौजूदा संदर्भ में महंगाई प्रबंधन से ज्यादा ग्राय को अधिक प्रोत्साहन देना चाहता है।

कम से कम दो कमजोरियाँ हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक ने अपेक्षाकृत स्थिर और सुविधापूर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है। पहली, भारत का सेवा प्रमुख खिलाड़ी अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़र्व बैंक की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में अधिक होगी, बजाय मूल्य के मोर्चे पर निगरानी रखने की अपनी मुख्य चिंता के। वर्तमान संदर्भ में शायद यह एक उचित रुख है, जबकि भारत की ग्राय रेट “निराशा” के दौर से उबरी है। रिज़र्व बैंक मौजूदा संदर्भ में महंगाई प्रबंधन से ज्यादा ग्राय को अधिक प्रोत्साहन देना चाहता है।

कम से कम दो कमजोरियाँ हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक ने अपेक्षाकृत स्थिर और सुविधापूर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है। पहली, भारत का सेवा

निर्यात (सर्विसेज एक्सपोर्ट) और दूसरी, ग्लोबल फायनेंशियल मार्केट्स के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न वित्तीय अस्थिरता की संभावना।

ट्रंप के शुल्कों ने सेवा क्षेत्र (सर्विसेज एक्सपोर्ट) को ध्यान में नहीं रखा है और शुल्क मुख्य रूप से माल निर्यात पर लगाए गए हैं। अगर ट्रंप अचानक सेवाओं के निर्यात पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, तो भारत को भारी झटका लग सकता है। हमारा माल निर्यात जी.डी.पी. का केवल 2 प्रतिशत है। सेवा निर्यात का हिस्सा कहीं अधिक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट को कम करने वाला कोई भी कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को पैरलाइज कर सकता है, पंगु बना सकता है। वैसे भी भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की प्रगति के कारण, अस्तित्व का संकट झेल रहा है। इन निर्यातों में कई ऐसी सेवाएँ हैं, जो एआई उपकरणों द्वारा दी जा सकती हैं, तथा निचले स्तर के सॉफ्टवेयर डवलपर्स और कोडर्स द्वारा किए गए काम को उपयोग में लिया जा सकता है।

2 5 3 सिख श्रद्धालु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाने का वीजा मिला है। उन्होंने बताया कि यह जल्था 10 अप्रैल को सुबह छह बजे वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। आधा समूह गुरुद्वारा पंजा साहिब और आधा गुरुद्वारा कर्तारपुर साहिब जायेगा। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को दोनों जगह ननकाना साहिब में एकत्र होंगे और 12, 13 और 14 अप्रैल

को बैसाखी मनाएंगे। जो श्रद्धालु पहले पंजा साहिब गए हैं, वे कर्तारपुर साहिब जाएंगे और जो कर्तारपुर साहिब गए हैं, वे पंजा साहिब जाएंगे। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को यह जल्था लाहौर पहुँचेगा और वहां गुरुद्वारा साहिब में नमन करने के बाद 19 अप्रैल को भारत वापस लौटेंगा। सरदार दलजीत सिंह सरना को जल्थे का प्रभारी बनाया गया है।

कैशलेस इलाज योजना में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया। मामले में सुनावई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बातपर आपत्ति जताई कि 8 जनवरी के आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया।

कोर्ट ने आगे कहा कि 8 जनवरी को दिए गए आदेश के बावजूद केन्द्र ने योजना को लागू नहीं किया, जो कि एक गंभीर

- सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

उल्लंघन है। सुनावई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि यह न केवल अदालत के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि एक लाभकारी कानून को लागू करने में भी देरी हो रही है। अदालत ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि यह उनका खुद का कानून है और यदि

योजना लागू नहीं की जाती तो लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि बीजिंग पीछे नहीं हटता तो अतिरिक्त 50 प्रतिशत टैरिफ बुधवार तक लागू किया जाएगा। “जैसे को तैसा” की इस प्रक्रिया की शुरुआत पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा चीन पर 3.4 प्रतिशत टैरिफ प्रदर्शनों से हुई, जिसका चीन ने तुरंत वैसा ही जवाब दिया था। अमेरिकी टैरिफ चीनी सामानों पर

‘बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं करेंगे’

प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों से कहा, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी

- ममता बनर्जी ने कहा, हमारा संदेश है “जियो और जीने दो” अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का हक नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ दूसरे की संपत्ति ली जा सकती है।

“जियो और जीने दो” का संदेश देना चाहिए। बंगाल में रहने वालों को सुरक्षा देना हमारा काम है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि अगर कोई आपको राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उकसाता है, तो कृपया ऐसा न करें। कृपया याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। अगर हम साथ रहेंगे, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। सीएम बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवनकाल में वहाँ जाती रहूँगी। भले ही आप मुझे गोली मार दें, आप मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे।

पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाया जाए

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। पैकेज्ड फूट पर चेतावनी लेबल लगाने की याचिका पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अगले तीन महीनों में सिफारिशों को लागू करें। एससी ने केंद्र से तीन महीने के भीतर एफएसएस लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन पर फैसला लेने को कहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पैकेज्ड फूड

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया।

के पैकेट पर चेतावनी की मांग करने वाली जगहों में दायर याचिका पर ये टिप्पणी की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनावई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियाँ हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें,आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या हैं और किस तरह का रैप होना चाहिए। उन्हें पैकेट पर कोई जानकारी नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एफएसएसएआई को तीन महीने के भीतर नए नियम में संशोधन पूरा करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।

अमेरिका ने 2 6 / 1 1 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा

तहव्वुर राणा को भारत ला रहा विमान देर रात तक भारत पहुंचेगा

- भारत से एक विशेष टीम तहव्वुर को लेने अमेरिका गई है।
- राणा के भारत आगमन के सम्बंध में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अहम मीटिंग की।
- राणा का विमान कहां लैंड करेगा, उसे कहां रखा जाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का रास्ता साफ हो गया था।

राणा ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई के विरुद्ध 13 फरवरी को दायर याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ अमेरिका में सभी अपीलों पर अदालती कार्यवाही पूरी होने तक उसे भारत को न सौंपा जाए। उसने तर्क दिया कि उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र की यतना विरोधी संधि का उल्लंघन है। राणा का कहना था कि उसे भारत में यातनाएं दी जा सकती है।

अमेरिकी शीर्ष अदालत द्वारा सोमवार को फैसला करने के लिए प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिये जाने के बाद उसे भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत से एक मल्टी-एजेंसी टीम अमेरिका गई थी और उसने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद की।

रिपोर्टों के अनुसार, 64 वर्षीय

पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा, पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। राणा लॉस एंजिल्स में अमेरिकी मेट्रोपॉलिटन डिट्रॉन सेंटर में 14 साल तक कैद रहा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2023 में भारत को उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन उसने शीर्ष अदालत में बार-बार प्रत्यर्पण रोकने के लिए याचिकाएं दायर की थीं, पर उसे सफलता नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने वाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में राणा के भारत में प्रत्यर्पण की घोषणा की थी।

राणा ने आतंकवादी हमले से पहले मुंबई में आतंकी हमलों के स्थानों को चिह्नित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रेकी और जासूसी की थी, उसने जिहादी सौदागदारी सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में राणा के भारत में प्रत्यर्पण की घोषणा की थी।

मुंबई में आतंकी हमलों के स्थानों को चिह्नित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रेकी और जासूसी की थी, उसने जिहादी सौदागदारी सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में राणा के भारत में प्रत्यर्पण की घोषणा की थी।

‘अब दांव पर वाणिज्य और व्यापार नहीं, वरन् ...

एशियाई वित्तीय संकट के बाद से एक ही दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी, हालांकि मंगलवार को कुछ हद तक सुधार हुआ।

फिर भी कुछ अर्थशास्त्री पूछ रहे हैं: यह स्थिति कब तक रहेगी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रुतियानचेन ने कहा, “चीन पहले से ही 60 प्रतिशत से अधिक के

टैरिफ दर का सामना कर रहा है- अगर यह 50 या 500 प्रतिशत तक बढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता”, इसके बजाय, शु ने चेतावनी दी, चीन भी इसी तरह से प्रतिशोध ले सकता है।

दांव अब सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं रह गए हैं। बल्कि वन, ताकत और विश्व में अपनी स्थिति दर्शाने का जरिया बन गए हैं।

26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे

नयी दिल्ली, 09 अप्रैल। नौसेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने फ्रांस से 63 हजार करोड़ रुपये की लागत से 26 मरीन राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकार ने मंगलवार को इन विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इन लड़ाकू विमानों के मिलने के बाद नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जायेगी। अभी वायु सेना के बेड़े में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है और विमानों की आपूर्ति में चार से पांच वर्ष का समय लग सकता है। अनुबंध के पैकेज में विमानों का रखा रखव, प्रशिक्षण और कलपुर्जों का देश में ही निर्माण भी शामिल है।

- सरकार ने 63 हजार करोड़ रु. के इस सौदे को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

क्षमता कई गुना बढ़ जायेगी। अभी वायु सेना के बेड़े में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं। सूत्रों ने बताया कि इस अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है और विमानों की आपूर्ति में चार से पांच वर्ष का समय लग सकता है। अनुबंध के पैकेज में विमानों का रखा रखव, प्रशिक्षण और कलपुर्जों का देश में ही निर्माण भी शामिल है।

बिहार में बिजली गिरने से 15 की मौत

पटना, 09 अप्रैल। बिहार में बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में बुधवार को बिजली गिरने की घटना में 15 लोगों की झुलसकर मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेगूसराय और दरभंगा में पांच-पांच, मधुबनी में तीन और समस्तीपुर में दो व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हुयी है।

बेगूसराय से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले में बिजली गिरने से मरने वाले पांच लोगों में एक महिला, एक

- सूत्रों के अनुसार बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से ये हादसे हुए हैं।

तीन वर्षीय बालिका शामिल है। इसके अलावा एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। दरभंगा में भी 5 लोगों के मरने की खबर है। इनमें एक दस वर्षीय बालक व एक महिला भी शामिल है। मधुबनी में तीन लोगों के मरने की जानकारी मिली है। इनमें से एक 19 वर्षीय युवती है।